

प्रेषक,

चन्द्र सिंह नपलच्याल,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 01 प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,  
गृह/लोक निर्माण/ आबकारी/ शहरी विकास /चिकित्सा स्वास्थ्य  
एवं परिवार कल्याण/ शिक्षा/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 02 विभागाध्यक्ष,  
पुलिस/लोक निर्माण/आबकारी/शहरी विकास/चिकित्सा स्वास्थ्य  
एवं परिवार कल्याण/शिक्षा/वित्त एवं परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड।

परिवहन अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 28, जून, 2016

विषय: मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति की संस्तुति के क्रम में राज्य सड़क सुरक्षा कार्ययोजना के अनुमोदन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं अनुश्रवण हेतु गठित 'सड़क सुरक्षा समिति' की संस्तुतियों के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में सड़क सुरक्षा बढ़ाने एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने हेतु कार्ययोजना अनुमोदित कर भारत सरकार को प्रेषित की जानी है।

2. उक्त समिति की संस्तुति के क्रम में दिनांक 27 नवम्बर, 2015 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित 'राज्य सड़क सुरक्षा एवं अनुश्रवण समिति' की बैठक में निर्देशित किया गया था कि तदनुसार अविलम्ब कार्ययोजना तैयार की जाय।

3. उक्त के संदर्भ में आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा विभिन्न हितबद्ध विभागों के समन्वय से तैयार कर शासन को उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना को परिशिष्ट के रूप में अनुमोदित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्ययोजना में संबंधित विभागों को दिये गये उत्तरदायित्वों/सड़क सुरक्षा समिति की संबंधित संस्तुतियों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि चूंकि कार्य योजना में सम्मिलित विभागों को सौंपे गये उत्तरदायित्वों का निर्धारण संबंधित विभाग के मूल उत्तरदायित्वों के अनुरूप ही किया गया है अतः कार्ययोजना के क्रियान्वयन पर होने वाले व्ययभार का वहन विभागों द्वारा अपने-अपने विभागीय आय-व्ययक के माध्यम से किया जायेगा। उक्त हेतु संबंधित विभाग अपने आय-व्ययक में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक परिशिष्ट।

भवदीय,

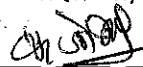
(चन्द्र सिंह नपलच्याल)  
सचिव।

क्रमशः पृष्ठ 2/पर

संख्या 391 / IX-1/2016 तददिनोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, सड़क सुरक्षा समिति, विज्ञान भवन एनेक्सी, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011.
2. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(प्रकाश चन्द्र जोशी)  
उप सचिव।

उत्तराखण्ड राज्य में सड़क सुरक्षा बढ़ाने एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कार्ययोजना।

**स्तम्भ-1 सड़क सुरक्षा प्रबन्धन- संस्थागत एवं क्षमता विकास**

क्र०सं०	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अवधि	अपेक्षित लक्ष्य	अभ्युक्ति
1	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एक सड़क सुरक्षा अनुश्रवण समिति का गठन किया जाना, जिसमें परिवहन, लोक निर्माण, चिकित्सा, गृह आदि विभागों के सचिव सम्मिलित होंगे।	परिवहन विभाग	-	-	अधिसूचना संख्या-316/IX-1/25/2015 दिनांक 27 अप्रैल, 2015 के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में लीड एजेंसी का गठन किया गया है।
2	राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया जाना।	परिवहन विभाग	-	-	अधिसूचना संख्या-663/IX-1/39/2014 दिनांक 09-12-2014 के अन्तर्गत मा० परिवहन मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है।
3	जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया जाना।	परिवहन विभाग	-	-	अधिसूचना संख्या-662/IX-1/39/2014 दिनांक 09-12-2014 के अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया गया है।
4	सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत कार्य योजना तैयार करना, जिसके अन्तर्गत विशिष्ट कार्य हेतु	परिवहन विभाग एवं अन्य सम्बन्धित	3 माह	-	

✓

	समयावधि निर्धारित किया जाना।	विभाग			
5	सड़क सुरक्षा निधि का गठन किया जाना, जिसके माध्यम से राज्य में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्य किये जायें।	परिवहन विभाग	6 माह	-	उत्तराखण्ड मोटरयान करधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा 8-क के अनुसार वाहनों पर ग्रीन सैस आरोपित किया गया है। अधिनियम की उक्त धारा में दिये गये प्राविधानों के अनुसार "उत्तराखण्ड शहरी परिवहन निधि नियमावली 2015" के प्रस्ताव पर मा10 मन्त्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त हो गया है, अग्रिम कार्यवाही गतिमान है।
6	राज्य एवं जनपद स्तर पर सड़क दुर्घटना सूचना तन्त्र का विकास किया जाना।	पुलिस विभाग परिवहन विभाग जिला प्रशासन	2 वर्ष	<p>1- सड़क दुर्घटनाओं के सूचना तंत्र के लिए एक Uttarakhand Police (Android Based Mobile application) को सम्पूर्ण राज्य में 02 वर्ष के अन्दर लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।</p> <p>2- पुलिस विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद में फेसबुक के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं के बारे में सूचना देना।</p> <p>3- विभिन्न विभागों- पुलिस, वन, परिवहन आदि के मध्य पुलिस विभाग द्वारा Integrated Wireless</p>	<p>1- Uttarakhand Police (Android Based Mobile application) को अभी पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य के गढ़वाल परिशेत्र के जनपद देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली एवं रुद्रप्रयाग में लागू किया गया है।</p> <p>2- चारधाम यात्रा के दौरान दुर्घटना एवं खराब मौसम के दौरान मोबाईल ब्लॉक सेवा का प्रयोग किया गया।</p>

				system विकसित किया जाना। 4- पुलिस विभाग द्वारा मोबाईल ब्लक मैसेजिंग सर्विस से सड़क दुर्घटना से सम्बन्धित समस्त Stakeholders को सूचित करना।	
7	प्रत्येक दुर्घटना के कारणों का इन्वेस्टिगेशन किया जाये, रिपोर्ट तैयार की जाये तथा इसके आधार पर पुनरावृत्ति सेकने के लिए आवश्यक उपाय किये जायें।	1. पुलिस विभाग 2. परिवहन विभाग 3. स्वयं सेवी संस्थायें	03 वर्ष	इस हेतु पृथक यातायात निदेशालय का गठन किया जाना होगा, जिसके लिए पुलिस विभाग द्वारा अलग से शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा।	-
8	निजी क्षेत्र में स्थापित चालक प्रशिक्षण स्कूलों का सीआईआरटी, आईडीटीआर आदि के माध्यम से तृतीय पक्ष ऑडिट कराया जाना।	परिवहन विभाग	प्रतिवर्ष	-	-

स्तम्भ-2 सुरक्षित सड़कों की स्थापना एवं अनुरक्षण

क्र०सं०	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अवधि	अपेक्षित लक्ष्य	अपेक्षित धनराशि लाख रुपये में	अभ्युक्ति
1	Indian Road Congress द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन न करने वाले आगणनों पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान न किया जाना।	लोक निर्माण विभाग	निरन्तर	-	-	सरकार को जो भी आगणन प्रेषित किये जाते हैं, वे आईआरसी एवं एमओआरडी के मानकों के अनुरूप तैयार किए जाते हैं।
2	सभी राज्य राजमार्ग एवं अन्य सड़कों पर IRS Standard के अनुसार रोड मार्किंग एवं साईनबोर्ड लगाया जाना।	लोक निर्माण विभाग	-	948.70 किमी० रोड मार्किंग 608.50 किमी० साईनेज	3475.37	निरन्तर कार्यवाही की जा रही है। 891 किमी० साईनेज कार्य एवं 430 किमी० रोड मार्किंग किया जा चुका है।
3	वर्तमान निर्मित सड़कों एवं निर्माणाधीन सड़कों का रोड सेपटी ऑडिट कराया जाना ऑडिट रिपोर्ट का अनुपालन किया जाना।	लोक निर्माण विभाग		84	-	एडीबी परियोजना के अन्तर्गत निर्मित 84 सड़कों का रोड सेपटी ऑडिट कराया जा चुका है।
4	राज्य राजमार्ग पर ब्लैक स्पॉट का चिन्हिकरण एवं निवारण।	लोक निर्माण विभाग		06	3020.00	आगणन तैयार किया जा रहा है।
5	राज्य राजमार्ग से मिलने वाले छोटे मार्गों के जंक्शनों का विकास।	लोक निर्माण विभाग		24	113.00	04 स्थलों का कार्य पूर्ण तथा 01 पर कार्यवाही गतिमान।
6	बस्तियों के सभी राजमार्ग पर विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ किया जाना।	स्थानीय निकाय	निरन्तर			वर्तमान में प्रदेश के सभी नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा राजमार्ग पर

						अपने निर्धारित क्षेत्र में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था की जा रही है। समुचित अनुरक्षण हेतु पृथक से निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं।
7	सड़कों के किनारे खतरनाक होर्डिंग्स/ऑब्जेक्ट हटाया जाना	शहरी विकास/लोक निर्माण विभाग	निरन्तर	286	300.00	लोक निर्माण विभाग की आख्या के अनुसार यह एक सतत् प्रक्रिया है। अभी तक 50 स्थानों पर कार्यवाही की गई है। शहरी विकास विभाग की आख्या के अनुसार-उत्तराखण्ड नगर निगम (विज्ञापन अनुज्ञा एवं विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली) नियमावली 2015 को लागू करार जाने हेतु आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त कर लिए गए हैं। नियमावली को अन्तिम रूप से लागू किए जाने हेतु विधिक प्रक्रिया अन्तिम चरण में है। स्थानीय निकायों द्वारा वर्तमान नियमों के अन्तर्गत होर्डिंग के बिना स्वीकृति लगे पाए जाने पर अथवा उनके खतरनाक होने की सूचना मिलने पर उनके हटाए जाने की कार्यवाही निरन्तर की जा रही है।
8	सड़कों के निर्माण, योजना, डिजाईन आदि में संलग्न अभियन्ताओं को Indian Academy of Highway Engineers आदि	लोक निर्माण विभाग		18	-	अभी तक 12 अभियन्ताओं द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है।

	संस्थाओं के माध्यम से सड़क सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण दिलाया जाना।					
9	साईकिल और नॉन मोटरसाईज्ड यातायात के लिए सभी राजमार्गों पर पृथक सड़क की व्यवस्था।	लोक निर्माण विभाग/शहरी विकास विभाग	-			लोक निर्माण विभाग की आख्या के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में नॉन मोटरसाईज्ड यातायात अधिक प्रचलित नहीं है। शहरी विकास विभाग की आख्या के अनुसार-वर्तमान में लागू नवीन योजना "अमृत" के अन्तर्गत प्रथम चरण में नगरीय क्षेत्र में, पृथक सड़क साईकिल और नॉन मोटरसाईज्ड यातायात के लिए (अमृत योजना में अनुमन्य), चयनित स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तावित नहीं की गई है। प्रथम चरण में जलपूर्ति, सीवर, ड्रेनेज, पार्क प्रस्तावित है।
10	रोड नेटवर्क की सुरक्षा में सुधार एवं अनुश्रवण हेतु एक विशेषज्ञ इकाई का गठन।	लोक निर्माण विभाग	-			दिनांक 04-12-2015 को शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया।
11	सड़कों पर Traffic Calming Measures यथा—Centre Verge, Railing, Grill on both side, caution sign, table top speed breaker, rumble strip आदि प्रभावी ढंग से लागू किया जाना।	लोक निर्माण विभाग	-	110 Nos.- Signage 36 km - Center Verge 317 Nos.- Rumble Strip 150.80 km -Crash	4376. 72	यह एक सतत् प्रक्रिया है। वर्तमान में निम्नलिखित अवयव उपलब्ध हैं:- 4 Km center verge, 36 Nos. Rumble strip/Speed breaker, 40.00 km Crash barrier 38 Nos. Zebra Crossing, 102 Nos. caution board 2600 No Delenator,



					4900 No Cat Eyes completed.
12	राजमार्गों में मिलने वाले छोटे मार्गों पर स्पीड ब्रेकर (स्पीड मैनेजमेंट मेजर) लगाना।	लोक विभाग निर्माण		barrier 48 Nos.- Zebra Crossing 231 Nos.- caution board 1208.40 Km- Praperts 5450 Nos.- Delimator 10000 Nos.- Cat Eye	07 राष्ट्रीय राजमार्गों एवं 01 राज्य राजमार्ग पर कार्य पूर्ण।
13	राज्य राजमार्गों पर ट्रक ले-बाई, बस बे-बाई एवं शेल्टर्स का निर्माण।	लोक विभाग निर्माण	01	—	ले-बाई का निर्माण देहरादून-ऋषिकेश मार्ग किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को 2-लेन से 4-लेन एवं 1-लेन से 2-लेन किये जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिये डीपीआर आदि की कार्यवाही गतिमान है। उक्त कार्य को 03 वर्ष में किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
14	लम्बी दूरी के वाहन चालकों के लिए राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर उच्च मार्ग सुविधा केन्द्र विकसित किये जावे एवं	लोक विभाग निर्माण	—	—	वर्तमान में पर्वतीय मार्गों पर रात्रि में वाहन संचालन प्रतिबन्धित है। इसके अतिरिक्त मुख्य मार्गों पर

	वालकों को विश्राम की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। इस हेतु परिवहन व्यवसायियों को शिक्षित किया जाए।					सड़क के किनारे निजी क्षेत्र में पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है।
15	दुर्घटना संभावित क्षेत्र में एक मॉडल सेफ हार्ड-वे का विकास किया जाना और उसके परिणामों का मूल्यांकन किया जाना।	लोक निर्माण विभाग	-	-	-	साईट चयन किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

संलग्न-3 सुरक्षित वाहन

क्र०सं०	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अवधि	अपेक्षित लक्ष्य	अपेक्षित धनराशि लाख रुपये में	अभ्युक्ति
1	वाहनों की नियमित जाँच हेतु ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन (Inspection and Certification Centre) की स्थापना, उनके तृतीय पक्ष ऑडिट की व्यवस्था करना।	परिवहन विभाग	प्रति 2 वर्ष में 01		1440.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ऋषिकेश में ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन की स्थापना हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से परामर्श के फलस्वरूप आईकैट को सम्मिलित किया गया है।</li> <li>आईकैट द्वारा प्रस्तावित भूमि का स्थल निरीक्षण दिनांक 04-11-2015 को ऋषिकेश में किया गया।</li> <li>आईकैट के माध्यम से प्रस्ताव तैयार कराते हुए शीघ्र ही</li> </ul>

						स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा।
2	वाहनों को स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रदान करने में संलग्न कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना।	परिवहन विभाग	निरन्तर			समय-समय पर एआरआई, आईआईपी आदि में प्रशिक्षण हेतु कार्मिकों को भेजा गया है।
3	तीव्र गति से वाहन संचालन की रोकथाम हेतु व्यवसायिक वाहनों में जीपीएस की स्थापना कराया जाना एवं राज्य/संभाग/उप संभाग स्तर पर कन्ट्रोल रूम की स्थापना।	परिवहन विभाग	2 वर्ष			
4	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के प्राविधानों के अन्तर्गत वाहनों में AIS 090 मानकों की रिफ्लेक्टिव टेप अनिवार्य किया जाना और वाहन किटनेस के समय इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।	परिवहन विभाग	निरन्तर			केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 104 के अन्तर्गत राज्य में रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य किया गया है।
5	भार वाहनों एवं बसों में अन्दर प्रोटेक्शन डिवाइस लगाया जाना और वाहन किटनेस के समय इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।	परिवहन विभाग	निरन्तर			केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के प्राविधानों का पालन किया जा रहा है।
6	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के प्राविधानों के अनुसार वाहनों में AIS मानकों के दर्पण लगावाया जाना और वाहन किटनेस के समय इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।	परिवहन विभाग	निरन्तर			केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के प्राविधानों का पालन किया जा रहा है।
7	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 93 में विहित मानकों से	परिवहन विभाग	निरन्तर			केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के प्राविधानों का पालन किया जा रहा है।

	बड़ी वाहनों के विक्रय कार्यवाही करना और वाहन फिटनेस के समय इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।						केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के प्राविधानों का पालन किया जा रहा है।
8	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 118 में विहित मानकों के अनुसार व्यवसायिक वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाया जाना और वाहन फिटनेस के समय इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।	परिवहन विभाग	निरन्तर				
9	मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 138 (2) के अन्तर्गत सार्सकिल एवं अन्य non-motorized वाहनों के लिए निर्देश जारी करना।	परिवहन विभाग	निरन्तर				
10	स्कूल बसों एवं स्कूली बच्चों को ले जाने वाले अन्य वाहनों की फिटनेस कड़ाई से किया जाना।	परिवहन विभाग	निरन्तर				

स्तम्भ-4 प्रवर्तन कार्यों का सुदृढीकरण एवं यातायात नियमों का अनुपालन कराया जाना

क्र०सं०	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अवधि	अपेक्षित लक्ष्य	अपेक्षित धनराशि लाख रुपये में	अभ्युक्ति
1	दो पहिया वाहन चालकों के लिए सम्पूर्ण राज्य में हैल्मेट पहनना अनिवार्य करना एवं इसका प्रचार-प्रसार करना।	परिवहन विभाग पुलिस विभाग	निरन्तर			जनपद देहरादून तथा हरिद्वार के शहरी क्षेत्रों में हैल्मेट पहनने की अनिवार्यता के लिये जागरूकता अभियान के तहत 70 प्रतिशत लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। हैल्मेट

						पहनने की अनिवार्यता के लक्ष्य को 100 प्रतिशत पूर्ण करने हेतु प्रयास जारी हैं। - वर्ष 2015 में बिना हैल्मेट वाहन चलाने वाले कुल 266123 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। वर्ष 2015 में अब तक के बिना सीट बेल्ट के 1803 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।
2	यात्री वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य किया जाना।	परिवहन विभाग पुलिस विभाग	निरन्तर			
3	राष्ट्रीय राजमार्गों एवं अन्य मार्गों पर गति की अधिकतम सीमा निर्धारित किया जाना तथा उसका प्रवर्तन किया जाना। इस हेतु परिवहन एवं पुलिस विभाग के प्रवर्तन दलों को स्पीड रज़ारगन एवं अन्य उपकरण उपलब्ध कराना।	परिवहन विभाग पुलिस विभाग	3 माह / निरन्तर			वर्ष में अब तक ओवरस्पीडिंग मामलों में 10194 चालान किये गए। राज्य में वर्तमान समय में स्पीड रज़ारगन-16, इन्टरसेप्टर-6 उपलब्ध हैं।
4	वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने वाले चालकों के विरुद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही किया जाना।	परिवहन विभाग पुलिस विभाग	निरन्तर			वर्ष 2015 में अब तक 4928 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।
5	यात्री वाहनों में क्षमता से अधिक सवासी लेकर चलने की प्रवृत्ति पर रोक लगाया जाना।	परिवहन विभाग पुलिस विभाग	निरन्तर			वर्ष 2015 में अब तक 18360 मामलों में कार्यवाही की गई।
6	भार वाहनों में ओवरलोडिंग की प्रवृत्ति पर रोक लगाया जाना।	परिवहन विभाग	निरन्तर			

7	व्यवसायिक वाहनों में ओवरलोडिंग की जाँच हेतु वे-इन मोशन ब्रिज की स्थापना किया जाना।	परिवहन विभाग लोक निर्माण विभाग	2 वर्ष			लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार- ओवरलोडिंग रोकने के लिए राज्य के Entry Point पर 02 Weigh in motion bridge लगाये गये हैं, जो हरिद्वार व ऊधमसिंहनगर जिले की उत्तर प्रदेश की सीमा पर लगे हैं।
8	राजमार्गों एवं अन्य मुख्य मार्गों पर खतरनाक ढंग से पार्क की गई वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही करना।	परिवहन विभाग पुलिस विभाग	निरन्तर			राज्य में माह अप्रैल 2015 से पुलिस द्वारा राजमार्गों एवं हाईवे पर गलत तरीके से पार्क किए गए 12193 वाहनों के चालान किए गए।
9	नशे की हालत में वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही किया जाना एवं ऐसे चालकों की जाँच हेतु परिवहन एवं पुलिस विभाग के प्रवर्तन दलों को एल्कोमीटर/ब्रेथ एनेलाईजर उपलब्ध कराया जाना।	परिवहन विभाग पुलिस विभाग	निरन्तर			वर्ष 2015 में अब तक नशे की हालत में वाहन चलाने के मामले में 1265 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। 225 व्यक्तियों की लाईसेन्स निरस्तीकरण की रिपोर्ट प्रेषित की गई। राज्य में वर्तमान में 116 ब्रेथ एनेलाईजर उपलब्ध हैं। 120 एल्कोमीटर क्रय करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।
10	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के अन्तर्गत हैडलाईट आधा काला करने का नियम नहीं है। अतः इस नियम का पालन कराये जाने और वाहनों को रात्री में लो-बीम पर वाहन चलाने हेतु प्रेरित करते हुए प्रवर्तन की कार्यवाही कराया जाना।	परिवहन विभाग	निरन्तर			वर्ष 2015 में अब तक 605 मामलों में कार्यवाही की गई।

11	नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनो/चालकों के चालानों का डाटाबेस तैयार किया जाना। इस हेतु सभी चालानों का प्रश्मन परिवहन विभाग के माध्यम से किया जाना ताकि अनुवर्ती अपराध करने वाले चालकों पर अधिक प्रश्मन शुल्क आरोपित किया जा सके।	परिवहन विभाग पुलिस विभाग	1 वर्ष			मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 27-11-2015 को हुई बैठक में परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा एक ही सॉफ्टवेयर के आधार पर चालान करने और डाटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
12	चालक लाईसेन्स जारी किए जाने सम्बन्धी व्यवस्था का सुदृढीकरण किया जाना।	परिवहन विभाग				
	(ए) शिक्षार्थी लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु आने वाले सभी आवेदकों की कम्प्यूटर के माध्यम से परीक्षा लिया जाना। इस हेतु कार्यालयों को आवश्यक हार्डवेयर उपलब्ध कराना।		1 वर्ष			दिनांक 07-12-2015 से सम्भागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून में ऑनलाईन शिक्षार्थी लाईसेन्स जारी करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है,
	(बी) लाईसेन्स जारी करने से पूर्व प्रत्येक आवेदक को 02 घन्टे का अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना।		6 माह			
	(सी) स्थायी लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु आने वाले आवेदकों की सिमुलेटर्स के माध्यम से परीक्षा लिया जाना। इस हेतु सभी कार्यालयों में सिमुलेटर की स्थापना।		5 कार्यालय प्रतिवर्ष			स्थायी लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु आने वाले आवेदकों की परीक्षा कम्प्यूटरीकृत रूप से लिए जाने हेतु परिवहन कार्यालय में सिमुलेटर क्रय की कार्यवाही गतिमान है। इस हेतु 06 सिमुलेटर क्रय का आदेश सम्बन्धित फर्म को निर्गत किया जा चुका है।
	(डी) चालकों की भौतिक रूप से परीक्षा हेतु कार्यालयों में ऑटोमेटेड ड्राईविंग ट्रैक्स		2 कार्यालय			

	की स्थापना किया जाना।		प्रतिवर्ष			
	(ई) सभी लाईसेन्सों के अभिलेखों का डिजीटाइजेशन/बैकलॉग किया जाना।		1 वर्ष			
13	तकनीकी (फ़ेसबुक/वाट्सएप आदि) का प्रयोग करते हुए विभाग एवं सड़क प्रयोक्ताओं के मध्य संवाद स्थापित कराया जाना और सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार किया जाना।	परिवहन विभाग पुलिस विभाग	3 माह			
14	सड़क सुरक्षा सन्देशों को एसएमएस आदि के माध्यम से प्रसारित किया जाना।	परिवहन विभाग पुलिस विभाग	3 माह			राज्य में सड़क सुरक्षा सन्देशों को प्रचारित करने हेतु प्रथम चरण में गढ़वाल परिक्षेत्र के 7 जनपदों देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली एवं रुद्रप्रयाग में मोबाईल बल्क मैसेजिंग सर्विस व्यवस्था स्थापित की गई है। सम्पूर्ण राज्य में भी लागू की जाएगी।
15	मुख्य नगरों में ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का आधुनिकीकरण, जिसके अन्तर्गत चौराहों पर सीसीटीवी, ई-चालान, रेडलाईट कैमरा एवं अन्य आधुनिक उपकरण सम्मिलित है, किया जाना।	पुलिस विभाग				राज्य में 40 स्थलों पर 95 फ़िक्स्ड कैमरे लगाने हेतु चिन्हीकरण किया गया है। प्रथम चरण में दो वर्ष के अन्तराल में 95 हाईरेजुलेशन से युक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने एवं क्रय करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर प्रेषित किया जायेगा।
16	परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग में प्रवर्तन दलों का सुदृढीकरण एवं बढ़ती वाहनों की संख्या के दृष्टिगत प्रवर्तन दलों	परिवहन विभाग पुलिस	निरन्तर			राज्य में वर्तमान में यातायात पुलिस बल में यातायात निरीक्षक-04, यातायात उ0नि0-16, हे0कानि0-57,



	में यथासंभव वृद्धि किया जाना।	विभाग				कानि0-252 मौजूद हैं। यातायात प्रबन्धन का कार्य कानून व्यवस्था में तैनात कर्मियों द्वारा किया जाता है वर्तमान में आबादी एवं वाहनों की बढ़ती संख्या तथा यातायात में नियुक्त कर्मियों की मौजूदा जनशक्ति की कमी को देखते हुए 576 पुलिस कर्मियों के पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।
17	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्गों से शराब की दुकानें हटाया जाना।	आबकारी विभाग	1 वर्ष			वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रतिवर्ष 05 प्रतिशत दुकानों को हटाये जाने का प्रस्ताव है।
18	फुटपाथ एवं सड़कों से अतिक्रमण हटाया जाना।	शहरी विकास विभाग लोक निर्माण विभाग	निरन्तर			स्थानीय निकायों द्वारा वर्तमान नियमों के अन्तर्गत फुटपाथ एवं सड़कों से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही निरन्तर की जा रही है।

L

स्तम्भ-5 शिक्षा एवं जागरूकता

क्र०सं०	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अवधि	अपेक्षित लक्ष्य	अभ्युक्ति
1	स्कूलों, पुलिस, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा रही सड़क सुरक्षा शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था का अनुश्रवण करते हुए सुधार करना और स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना।	पुलिस विभाग परिवहन विभाग शिक्षा विभाग			
2	स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा विषय पर चैप्टर सम्मिलित किया जाना।	शिक्षा विभाग	6 माह		
3	टीचर्स ट्रेनिंग के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा विषय को भी सम्मिलित किया जाना।	शिक्षा विभाग	6 माह		
4	विभिन्न कार्यक्रमों यथा-रैली, स्ट्रीट ड्रिल, पपेट शो, सेमिनार आदि के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु जागरूकता अभियान चलाना।	परिवहन विभाग पुलिस विभाग	निरन्तर		
5	सिनेमाघरों में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित लघु फिल्म अनिवार्य दिखाया जाना।	परिवहन विभाग मनोरंजन कर विभाग	निरन्तर		
6	सरकारी भवनों, बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशन, एअरपोर्ट आदि पर सड़क सुरक्षा सम्बन्धी होर्डिंग्स का प्रदर्शन।	परिवहन विभाग यातायात पुलिस	निरन्तर		
7	सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार एवं लोगों को जागरूक करने हेतु मीडिया का सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से वर्कशॉप का आयोजन।	परिवहन विभाग पुलिस विभाग सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	वर्ष में 02 कार्यशाला		

8	व्यवसायिक वाहन चालकों का नियमित दृष्टि/स्वास्थ्य परीक्षण।	परिवहन विभाग चिकित्सा विभाग	प्रत्येक 06 माह में एक बार		
9	दुर्घटना होने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को तत्काल प्रथम उपचार उपलब्ध कराना और घायल को अस्पताल तक पहुंचाने वाले व्यक्ति का उत्पीड़न न किया जाना। इस हेतु चिकित्सकों एवं पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाया जाना।	पुलिस विभाग स्वास्थ्य विभाग	निरन्तर		
10	प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह में स्कूलों, सरकारी उपक्रमों तथा उद्योगपतियों का सहयोग लिया जाना।	पुलिस विभाग परिवहन विभाग	प्रतिवर्ष 100		
11	राज्य परिवहन निगम एवं निजी क्षेत्र के व्यवसायिक वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा सम्बन्धी पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना।	परिवहन विभाग	प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार		

संलग्न-6 आकस्मिक सहायता / सुविधा

क्र0सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अवधि	अपेक्षित लक्ष्य	अभ्युक्ति
1	सरकारी चिकित्सालयों में ट्रॉमा सुविधाओं का विकास।	स्वास्थ्य विभाग	02 प्रतिवर्ष	वर्तमान में कुल 09 ट्रॉमा सेन्टर में से 06 कार्यशील है, जबकि स्टॉफ की कमी के कारण 03 कार्यशील नहीं है। सभी चिकित्साधिकारियों को उक्त ट्रॉमा सेन्टर को कार्यशील बनाने के निर्देश दिये गये हैं।	
2	प्रत्येक 50 किमी0 की दूरी पर ट्रॉमाकेयर सेन्टर्स की स्थापना एवं उनका सुदृढीकरण।	स्वास्थ्य विभाग	प्रत्येक वर्ष 3-4 सुविधाओं का सुदृढीकरण	कोटद्वार एवं उत्तरकाशी में सीटी स्कैन मशीन की कार्यवाही गतिमान है।	
3	बचाव एवं चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के दृष्टिगत एम्बुलेन्स फ्लीट तैयार किया जाना और एकल टोलफ्री हैल्पलाईन नम्बर की स्थापना।	चिकित्सा विभाग	निरन्तर	टोल फ्री नम्बर 108 पूर्व से कार्यरत है।	
4	राज्य राजमार्गों पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के निकट एम्बुलेन्स एवं क्रेन आदि की व्यवस्था करना।	चिकित्सा विभाग पुलिस विभाग	निरन्तर	टोल फ्री नम्बर 108 पूर्व से कार्यरत है तथा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध करायी जा रही है। जहां तक रेस्क्यू वाहन का प्रश्न है यह कार्य पुलिस विभाग द्वारा किया जा रहा है।	
5	राजमार्गों के निकट कार्य करने वाले व्यक्तियों, स्वयंसेवियों एवं ग्रामीणों को प्रथम उपचार के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना।	चिकित्सा विभाग	मासिक कैम्प	रेड क्रॉस सोसाएटी एवं चिकित्सा विभाग के मास्टर ट्रेनर द्वारा ब्लाक स्तर तक प्रशिक्षण दिया जायेगा।	
6	चिकित्सकों एवं तकनीकश्रियनों को प्राथमिक उपचार एवं आकस्मिक स्थिति के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना।	चिकित्सा विभाग	30 कार्मिक प्रति 03 माह	प्रस्ताव को वर्ष 2016-17 के बजट में सम्मिलित किया जा रहा है।	
7	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के	परिवहन	त्रैमासिक कैम्प		

	प्राविधानों के अन्तर्गत सभी भारी वाहन चालकों को प्राथमिक उपचार सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना और वाहनों में प्रथम उपचार पेटिका अनिवार्य रूप से लगवाया जाना।	विभाग चिकित्सा विभाग			
8	उत्तराखण्ड परिवहन निगम के चालकों एवं परिचालकों को प्रथम उपचार के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना।	परिवहन विभाग चिकित्सा विभाग		प्रत्येक 03 वर्ष में एक बार	
9	दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र में एक मॉडल इमरजेंसी केयर सुविधा का विकास करना।	चिकित्सा विभाग		निरन्तर	प्रस्ताव को वर्ष 2016-17 के बजट में सम्मिलित किया जा रहा है।

(सी. एस. नूपलध्याल)  
 सचिव  
 परिवहन एवं राज्य सार्वजनिक विभाग  
 उत्तराखण्ड शासन